Journal of Social Issues and Development (JSID)
(Himalayan Ecological Research Institute for Training and Grassroots Enhancement (HERITAGE)
ISSN: 2583-6994 (Vol. 3 & 4)
Special Combined Issue (September 2025 — April 2026. pp. 186-194)

अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के प्रभाव का अध्ययन

राजबीर सिंह दलाल*
सुनील कुमार**
राजदीप सिंह***

परिचय

अंत्योदय अन्न योजना, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसका शुभारंभ वर्ष 2000 में उन परिवारों के लिए किया गया जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीब और वंचित परिवारों को सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर भूख और कुपोषण की समस्या का समाधान करना था। प्रारंभिक चरण में यह योजना 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में विस्तारित कर करोड़ों परिवारों तक पहुँचाया गया। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूँ) मासिक आधार पर प्रदान किया जाता है (Kamble, 2024)।

भारत में भूख और कुपोषण की समस्या लंबे समय से सामाजिक–आर्थिक विकास में बाधक रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति यह दर्शाती है कि करोड़ों लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अल्पपोषण और कुपोषण की उच्च दरें दर्ज की गई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गरीब परिवारों के लिए सुलभ और किफायती

* विभागाध्यक्ष, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा)–125055
** शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा)–125055
*** शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा (हरियाणा)–125055

खाद्य सुरक्षा योजनाएँ आज भी अनिवार्य हैं (Press Information Bureau, 2025)।

इस योजना का वैचारिक आधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' दर्शन से गहराई से जुड़ा है। उपाध्याय ने 'अंत्योदय' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को विकास का आधार बताया। उनका मानना था कि जब तक समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तब तक कोई भी विकास नीति अधूरी है। उनका एकात्म मानववाद दर्शन (Integral Humanism) सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता, और समग्र मानव विकास पर बल देता है (Misra, 2021; Surinder Singh, 2021)। इसी विचारधारा के अनुरूप, अंत्योदय अन्न योजना न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक समावेशन और समानता की दिशा में भी योगदान देती है।

पंडित उपाध्याय के अनुसार, विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल की सीमाओं को रेखांकित करते हुए भारतीय मूल्यों पर आधारित स्वदेशी आर्थिक नीति का समर्थन किया, जो विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित हो (Hareet Kumar Meena & Dhayal, 2025; Sunita, 2024)। इसी दृष्टिकोण के कारण, अंत्योदय अन्न योजना भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'अंतिम व्यक्ति' तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

शोध की आवश्यकता

शोध की दृष्टि से यह अध्ययन आवश्यक है क्योंकि यह समझने का अवसर देता है कि अंत्योदय अन्न योजना किस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से प्रेरित होकर भारत में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को पूरा करती है। इस अध्ययन का उद्देश्य योजना के ऐतिहासिक विकास, क्रियान्वयन और इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, साथ ही यह विश्लेषण करना है कि अंत्योदय दर्शन के तत्वों ने इसकी संरचना और नीति निर्माण को कैसे प्रभावित किया है (Mohar Singh & Yog Raj, 2024; Sharma & Nain, 2018)। यह शोध नीति–निर्माताओं और अकादमिक जगत के लिए यह समझने में सहायक होगा कि विचारधारात्मक आधार पर निर्मित योजनाएँ किस प्रकार सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों को साकार करने में सहायक हो सकती हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन भारतीय समाज के उन मूल्यों पर आधारित है जो सबसे वंचित व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने पर बल देते हैं। उपाध्याय का 'अंत्योदय' विचार यह मानता है कि राष्ट्र की प्रगति तभी सार्थक हो सकती है जब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे। उन्होंने स्पष्ट किया कि

आर्थिक नीतियों और योजनाओं की सफलता का आकलन केवल उत्पादन और समृद्धि के आँकड़ों से नहीं बल्कि उस गरीब और वंचित व्यक्ति की स्थिति से किया जाना चाहिए, जो अक्सर विकास से बाहर रह जाता है (Kamble, 2024; Sunita, 2024)। यह दृष्टिकोण केवल गरीबी उन्मूलन तक सीमित नहीं बल्कि एक समावेशी, आत्मनिर्भर और न्यायसंगत समाज के निर्माण की ओर संकेत करता है।

एकात्म मानववाद उपाध्याय के विचारों की दार्शनिक आधारशिला है। यह दर्शन व्यक्ति को केवल आर्थिक इकाई के रूप में नहीं बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समन्वित स्वरूप के रूप में देखता है। उपाध्याय का मत था कि पूँजीवाद की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति और साम्यवाद की राज्य–प्रधानता, दोनों ही मानव जीवन के समग्र विकास की अनदेखी करते हैं, क्योंकि वे या तो लोभ को बढ़ावा देते हैं या व्यक्तिगत गरिमा को नष्ट कर देते हैं (Misra, 2021; Singh, 2021)। इसके विपरीत, एकात्म मानववाद व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच संतुलन स्थापित कर समग्र विकास की राह सुझाता है, जहाँ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ भौतिक प्रगति भी समान रूप से महत्वपूर्ण होती है (Meena & Dhayal, 2025)।

सामाजिक न्याय और समान अवसर का विचार भी उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का केंद्र है। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत को विकास का ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो पश्चिमी पूँजीवादी या साम्यवादी मॉडलों की नकल न हो, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो (Sharma & Nain, 2018; Singh & Raj, 2024)। इसके तहत उन्होंने विकेंद्रीकरण, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और लघु उद्योगों के संवर्द्धन पर बल दिया, ताकि समाज के कमजोर तबकों को आत्मनिर्भरता और आजीविका के अवसर मिल सकें। उनका विचार था कि वास्तविक सामाजिक न्याय तभी संभव है जब आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक परंपराएँ एक–दूसरे के पूरक हों (Surinder Singh, 2021)।

उपाध्याय की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि स्पष्ट रूप से गरीबोन्मुखी थी। वे मानते थे कि विकास का केंद्र बिंदु व्यक्ति और उसका उत्थान होना चाहिए, न कि केवल औद्योगिक उत्पादन या शहरीकरण (Sunita, 2024)। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों, लघु उद्योगों और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर न केवल गरीबी कम की जा सकती है बल्कि एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की स्थापना भी की जा सकती है (Kamble, 2024; Meena & Dhayal, 2025)। यही सोच आज की कई योजनाओं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जो उनके अंत्योदय दर्शन की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है (Press Information Bureau, 2021, 2025)।

अंततः, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन आधुनिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ है। उनका 'अंत्योदय' विचार सरकार की कई योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण

आजीविका मिशन और ग्राम कौशल योजनाओं में निहित है, जिनका लक्ष्य ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक अवसर प्रदान करना है (Press Information Bureau, 2025)। इन योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता के तत्व उनके एकात्म मानववाद की जीवंत झलक प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, उपाध्याय का दर्शन केवल वैचारिक विमर्श नहीं बल्कि भारतीय विकास नीति की दिशा तय करने वाला जीवंत सिद्धांत बन चुका है, जो आज भी समावेशी और न्यायसंगत विकास के लिए प्रासंगिक है (Sunita, 2024; Sharma & Nain, 2018)।

अंत्योदय अन्न योजनाः स्वरूप और क्रियान्वयन

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) का शुभारंभ वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले सबसे गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। प्रारंभिक चरण में, योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई, जिन्हें प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल और गेहूँ) अत्यंत कम मूल्य पर प्रदान किया गया। इस योजना की मूल भावना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित थी, जो 'अंतिम व्यक्ति' तक विकास और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है (Sunita, 2024)।

इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पोषण में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना को पहले राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, और बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी से नीचे के पात्र परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज प्रति परिवार 3 किलो की दर से चावल और 2 किलो की दर से गेहूं जैसे खदान उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल यह स्कीम भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लागू है। 30 जून 2023 तक, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुल 80.10 करोड़ लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभ ले रहे हैं। इसमे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के 8.95 करोड़ लाभार्थी तथा प्राथमिकता श्रेणी के 71.15 करोड़ लाभार्थी, भारत के 5.45 लाख उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से योजना का लाभ ले रहे हैं। राज्यसभा में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लिखित उत्तर (30 जून 2023)।

योजना के पात्रता मानदंड को विशेष रूप से कमजोर और वंचित समूहों के लिए डिजाइन किया गया। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, भूमिहीन श्रमिक, वृद्ध, विकलांग व्यक्ति, विधवाएँ और अनाथ शामिल किए गए। समय–समय पर राज्य सरकारों ने अपने स्थानीय संदर्भ के अनुसार पात्रता मानदंडों को अद्यतन किया ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके (Kamble, 2024)। यह दृष्टिकोण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार से मेल खाता है जिसमें उन्होंने आर्थिक और सामाजिक नीतियों को

देशज आवश्यकताओं और कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर बल दिया (Meena & Dhayal, 2025)।

खाद्यान्न वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से लागू की गई। पात्र लाभार्थियों को पहचान पत्र (राशन कार्ड) प्रदान कर विशेष मूल्य पर गेहूँ और चावल उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार, खाद्य अनाज की आपूर्ति और सब्सिडी का प्रावधान करती है, जबकि राज्य सरकारें वितरण, लाभार्थियों की पहचान और निगरानी की जिम्मेदारी निभाती हैं। यह दोहरी भूमिका सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों तक सहायता पारदर्शी तरीके से पहुंचे (Kamble, 2024; Singh, 2021)।

राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका इस योजना में परस्पर पूरक रही है। केंद्र सरकार खाद्यान्न की आपूर्ति, वित्तीय प्रावधान और नीति–निर्माण करती है, जबकि राज्य सरकारें लाभार्थियों का चयन और वितरण प्रणाली का संचालन करती हैं। विभिन्न राज्यों ने तकनीकी हस्तक्षेपों (जैसे ई–पॉइंट ऑफ सेल मशीनें और बायोमेट्रिक सत्यापन) को लागू कर भ्रष्टाचार और अपात्र लाभार्थियों की समस्या को कम करने का प्रयास किया है (Ashok, 2022)।

वर्तमान समय में, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की संख्या और उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है (Press Information Bureau, 2025)। हाल के वर्षों में, योजना के सुधार और डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। राशन कार्डों का आधार से लिंक करना, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, और ई–राशन वितरण पोर्टल जैसी पहलें लागू की गई हैं, जिससे अपात्र लाभार्थियों की पहचान रोकी जा सके और वितरण अधिक पारदर्शी हो सके। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अवधारणा को बढ़ावा देकर लाभार्थियों तक प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया (Ashok, 2022)।

अंत्योदय अन्न योजना का वर्तमान स्वरूप केवल खाद्यान्न वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण आजीविका सृजन, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल पारदर्शिता के माध्यम से एक समग्र कल्याणकारी मॉडल का रूप ले चुका है। यह योजना न केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से मूर्त रूप देती है, बल्कि भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है (Sunita, 2024; Meena & Dhayal, 2025)।

अंत्योदय दर्शन का योजना पर प्रभाव

अंत्योदय अन्न योजना के उद्देश्यों और संरचना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह दर्शन, 'अंतिम व्यक्ति' तक विकास पहुँचाने की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें यह माना गया है कि समाज का वास्तविक

उत्थान तभी संभव है जब सबसे वंचित और गरीब वर्ग को विकास प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए (Sunita, 2024)। उपाध्याय का एकात्म मानववाद, जो मानव जीवन के भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करने की बात करता है, अंत्योदय अन्न योजना के वितरण तंत्र और लक्ष्यों में परिलक्षित होता है (Surinder Singh, 2021)। इस दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की सुविधा प्रदान करना है।

गरीब और वंचित वर्ग तक पहुँच बनाने में उपाध्याय के विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनका मानना था कि सरकारी नीतियाँ तभी प्रभावी होंगी जब वे भारतीय समाज की मौलिक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक जड़ों पर आधारित हों, न कि पश्चिमी औद्योगिक मॉडल पर (Hareet Kumar Meena & Dhayal, 2025)। इस दर्शन का प्रभाव योजनाओं के क्रियान्वयन में इस रूप में देखा जा सकता है कि अंत्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर न केवल भूख और कुपोषण को कम करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रेरित करती है (Mohar Singh & Yog Raj, 2024)।

'अंतिम व्यक्ति' तक सस्ते खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास, उपाध्याय की विचारधारा के मूल में हैं। उन्होंने बार–बार इस बात पर बल दिया कि राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मापदंड वह व्यक्ति है जो समाज की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है (Kamble, 2024)। इस विचारधारा के परिणामस्वरूप, योजना में प्राथमिकता ऐसे परिवारों को दी गई है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वृद्धजन, विकलांग, भूमिहीन मजदूर और अन्य वंचित समूह शामिल हैं (Press Information Bureau, 2021)।

सामाजिक समावेशन और खाद्य सुरक्षा की दिशा में अंत्योदय दर्शन ने नीतिगत दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। एकात्म मानववाद की अवधारणा, जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों को संतुलित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि योजना केवल कल्याणकारी पहल तक सीमित न रहकर, समाज में आत्मनिर्भरता और सहभागिता की भावना भी उत्पन्न करे (Sharma & Nain, 2018)। इसी कारण, सरकारी वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण और पारदर्शी निगरानी जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि अंत्योदय के मूल उद्देश्य को मजबूती दी जा सके (Gurram Ashok, 2022)।

नीति–निर्माण में उपाध्याय की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 'जनकल्याणकारी दृष्टिकोण' अपनाते हुए, अंत्योदय अन्न योजना केवल सब्सिडी प्रदान करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह लाभार्थियों को कौशल विकास, महिला स्व–सहायता समूहों (SHGs) के गठन और सूक्ष्म–उद्यमिता को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों से भी जोड़ती है (Press Information Bureau, 2025)। यह दृष्टिकोण उपाध्याय की इस मान्यता के अनुरूप

है कि राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब आर्थिक विकास सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ा हो (Rahul Kumar Misra, 2021)।

योजना की संरचना में अंत्योदय सिद्धांत का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह विकेंद्रीकृत, सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण उपाध्याय की उस अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें विकास का लाभ सबसे पिछड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य केवल संख्यात्मक लाभ नहीं, बल्कि भौगोलिक और सामाजिक समावेशन भी सुनिश्चित करना है।

'अंतिम व्यक्ति' तक आर्थिक अवसर और खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए DAY-NRLM ने कई नवाचार किए हैं। 2021 तक, 55,079 बीसी सखी (बिजनेस करेस्पोंडेंट) को तैनात किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, सरकारी योजनाओं के भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएँ पहुंचाती हैं। 2025 तक, SHG उत्पादों के विपणन के लिए Flipkart Samarth, Amazon Saheli, Meesho और e-SARAS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नेटवर्क तैयार किया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में पहुंच मिली।

इस प्रकार, योजना न केवल आर्थिक दृष्टि से महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त कर रही है, बल्कि सामाजिक समावेशन और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। SHG के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय, जीवनस्तर और आत्मनिर्भरता में जो प्रगति हुई है, वह दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के वास्तविक क्रियान्वयन का प्रमाण है। नीति–निर्माण के स्तर पर भी यह दर्शन प्रभावी रहा है, क्योंकि सरकारी नीतियाँ अब विकेंद्रीकृत सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी और स्वदेशी संसाधनों पर आधारित आर्थिक विकास पर जोर दे रही हैं।

चुनौतियाँ और सुधार की संभावनाएँ

यद्यपि अंत्योदय अन्न योजना ने गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की समस्या एक प्रमुख बाधा है। कई बार लाभार्थियों की सूची में अपात्र व्यक्तियों का नाम जुड़ जाता है जबकि वास्तविक जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाते हैं (Kamble, 2024)। इससे योजना का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ता है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है (Sunita, 2024)।

एक अन्य चुनौती लाभार्थियों में जागरूकता और सूचना की कमी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग योजना की पात्रता, लाभ और प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे वे इसका लाभ नहीं उठा पाते (Meena & Dhayal, 2025)। वितरण नेटवर्क की निगरानी और तकनीकी

खामियाँ भी योजना की दक्षता को प्रभावित करती हैं, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में तकनीकी त्रुटियों के कारण खाद्यान्न वितरण में देरी और अनियमितता (Ashok, 2022)।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु कई सुधार प्रस्तावित किए जा सकते हैं। सबसे पहले, राशन वितरण का डिजिटलीकरण और आधार लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है, जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सके और वास्तविक जरूरतमंद तक लाभ पहुँच सके (PIB, 2025)। स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है ताकि भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों और सामाजिक लेखा–परीक्षा की प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है (Sharma & Nain, 2018)।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त बनाना भी आवश्यक है, ताकि वे किसी भी समस्या की शिकायत सीधे दर्ज कर सकें और उसका शीघ्र समाधान हो (PIB, 2021)। महिला स्व–सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देना भी योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को बढ़ा सकता है (PIB, 2025)।

इन सुधारात्मक उपायों को अपनाकर अंत्योदय अन्न योजना को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन न केवल सैद्धांतिक रूप में बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी साकार हो। इस प्रकार, योजना न केवल भूख और गरीबी कम करने में सफल होगी बल्कि सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे भारत में 'अंतिम व्यक्ति' का सशक्तिकरण संभव होगा (Surinder Singh, 2021)।

निष्कर्ष और सुझाव

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय दर्शन और एकात्म मानववाद भारतीय कल्याणकारी नीतियों के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान को रखता है। अंत्योदय अन्न योजना इसी विचारधारा को व्यावहारिक रूप देते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यह योजना न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक न्याय के साथ–साथ व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन जीने में भी सहायक है। योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ कदम आवश्यक हैंः वितरण और लाभार्थी चयन में डिजिटल ट्रैकिंग व आधार–लिंक्ड तंत्र की मजबूती, SHGs और ग्राम संगठनों की निगरानी भूमिका का विस्तार, कौशल विकास को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना। एकात्म मानववाद की समग्र दृष्टि केवल आर्थिक उत्थान तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक

मूल्यों और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से भी मेल खाती है। यदि निगरानी और पारदर्शिता पर बल दिया जाए, तो अंत्योदय अन्न योजना भूखमुक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण साधन बन सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Ashok, G. (2022). Minimum government and maximum governance: Empowering the impoverished through Digital India campaign. *Indian Journal of Public Administration, 68*(3), 381–396. https://doi.org/10.1177/00195561221102409

Kamble, S. A. (2024). The Antyodaya philosophy: Government plan to rural development and rural livelihood security. *Aksharasurya: Peer-Reviewed, Multi-Lingual E-Journal, 4*(6), 119–121. https://doi.org/10.5281/zenodo.13725490

Meena, H. K., & Dhayal, S. (2025). Integral humanism and the SDGs: A pathway to balanced human development. *The Social Science Review, 3*(2), 65–70. https://doi.org/10.70096/tssr.250302011

Misra, R. K. (2021). Economic thought of Pt. Deen Dayal Upadhyaya. *International Journal of Humanities and Social Sciences, 10*(2), 317–320.

Press Information Bureau. (2021, December 31). Key initiatives and achievements of Ministry of Rural Development during the year 2021. *Ministry of Rural Development, Government of India.* https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1786672

Press Information Bureau. (2025, March 18). Target achieved under Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission. *Ministry of Rural Development, Government of India.* https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112203

Sharma, S. K., & Nain, A. (2018). Integral humanism of Deen Dayal Upadhyaya and its contemporary relevance. *The Indian Journal of Political Science, 79*(1), 13–20.

Singh, S. (2021). Decoding the integral humanism philosophy of Pandit Deendayal Upadhyay. *Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science, 10*(7), 102–105. https://www.questjournals.org

Singh, M., & Raj, Y. (2024). Deendayal Upadhyaya's contribution for building of modern Bharat: An analysis. *Hill Quest: A Multidisciplinary, National Refereed/Peer-Reviewed Journal, 11*(2), 65–67.

Sunita, D. (2024). *Deendayal Upadhyay's concept of Antyodaya and analysis of economic policy.* New Delhi: Apical Book Agency.